

ईवीएम का औपित्य

आम चुनाव, 2024 के लिए मतदान की शुरूआत हो चुकी है। देश के 17 राज्यों और 7 संघसासित क्षेत्रों की 102 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। जनादेश का एक हिस्सा उन ईवीएम में ही दर्ज हो चुका है, जिन पर अधिकतर विपक्षी दल प्रलाप कर रहे हैं। बेदल चुनावी दौड़ में शामिल हैं, उनके साथ और विधायक चुने जाने हैं, लेकिन वे इवीएम पर अब भी संरेख कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी बाड़ा ने यहाँ तक दावा किया है कि यदि ईवीएम में गडबड़ी नहीं की जाए है, तो भाजपा को 180 से कम सीटें मिलेंगी। यानी विपक्षी गठबंधन ईडिया मुगालों में है कि ईवीएम के जरिए ही जो मतदान होगा, उससे जनादेश उड़ें ही मिलने वाला है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, अंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, अरंगंजाब के आदि राज्यों में गैर-भाजपा दलों की भी सरकारें हैं, जो ईवीएम के जरिए ही बनी हैं। चुनावी पराया से पूर्व राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में भी 2018 में कांग्रेस सतारूढ़ हुई थी। तब भी मतदान ईवीएम के जरिए ही हुआ था। एक बार फिर यह मामला सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन है। दो व्यापारीओं की खंडिटों पर नैफैसला सुनिश्चित रखा है। दरअसल सावल यह है कि विषय का दोला दोला क्यों है? सर्वैधानिक व्यवस्थाओं के ही खिलाफ़ क्यों है? ईवीएम का इस्तेमाल छोड़ कर मतदानों वाले मतदान के पायांगकाल की ओर लौटाना क्यों चाहता है? हालांकि बूथ थप्पने, लौटने और फर्जी मतदान के उस दौर को सर्वोच्च अदालत खारिज कर चुकी है।

ईवीएम की शुरूआत कांग्रेस नेतृत्व की यूपी सरकार के ही दौरान हुई थी। इसके बाद दौर से लेकर आज तक करीब 340 करोड़ मतदान आपने संघविधानिक भागीदार का इस्तेमाल कर चुके हैं और 4 लोकसभा चुनावी ईवीएम के जरिए सम्पन्न कराए जा चुके हैं। 26 विधानसभा चुनावों और एक लोकसभा चुनाव में वीवीपैट पर्सी का भी इस्तेमाल किया जा चुका है। इक आम चुनाव में 55 लाख से अधिक ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है और करीब 1.5 करोड़ चुनावकर्मी मतदान प्रक्रिया में विस्तार लेते हैं। एक विशेष पार्टी के पक्ष से यह अपने एक विशेष पार्टी के पक्ष में तक यह दिया जाए और इन्हें चुनावकर्मी एक साथ प्रट हो जाए, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। ईवीएम किसी लैटेटेप, कम्युटर अथवा ईंटरेंट नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं है, उसे कहीं करना या छोड़ना भी संभव नहीं है, अलबात मरीन से तकीनी खराबी जूर का आ सकता है। उस वित्ती में ईवीएम सरकार ने उत्तरवाली को लारदारी व्यवस्था है। चुनाव आयोग ने अदालत में आना सम्पूर्ण पक्ष रखा है। वीवीपैट पर्सी और वीटिंग के आपसी मिलान पर भी सम्पूर्णरूप दिया है। पर्सी 7 सेकंड के लिए दिखती है। उसके बाद पर्सी मरीन में ही चली जाती है। न्यायिक पीठ को चाहा गया कि पर्सी को मतदान को देने जोगिम का कम है। इससे गोपनीयता भंग होती है और निकालने पर पर्सी का दुर्लभयोग भी किया जा सकता है। व्यापिकाकर्ता एडीआर ने मतदान और पर्सी की 100 फोसाई छ्रॉस चेकिंग की मांग की है। अब चुनाव की निपक्षता, ईमानदारी बरकरार रहे, मतदानाओं के जेहन में लेशमात्र भी सदैर नहीं होना चाहिए और आयोग की सर्वैधानिक स्वयंचयता भी बनी रहे, तब संदर्भ में अदालत ने तकिया देना है। ईवीएम का लेकर अक्सर प्रलाप मचाया जाना रहा है और चुनाव आयोग को भी कठिन रहा। यह विविध रूपों से खड़ा किया जाता रहा है, यह प्रवृत्ति दुष्प्राप्त है। आयोग ने ईवीएम को हैक करने वा उत्तर से सिस्टम से छेड़छाड़ करने के महेनजर सभी राजनीतिक दलों को अमरित विकाया था, कुछ लकड़ गए थे, लोकन कोई भी आपत्ति नहीं उठाए तो कोई विवाह कर रहा है। इसलिए वर्ष 2019 में और इस बार वर्षों में इन्हें सरकारी विषयों की विषयां आना नहीं कर रहे हैं। इसलिए किसान, मजदूर, कर्मचारी बैंकरार यावाओं खोटे व्यापारियों वाले भी उनके आपत्ति में रुचि रखते हैं। उन्हें एसो कुछ भी नहीं दिया। इसलिए वर्ष 2019 में और इस बार वर्षों में अपने वक्ष के बायों को विषयां आना नहीं कर सकती है? न्यायिक पीठ के सामने चुनाव आयोग ने खुलासा किया कि 4 करोड़ ईवीएम वोट और बीवीपैट पर्सीयों के मिलान कराए गए हैं। बहरहाल अदालती फैसले की प्रतीक्षा है।

सावधानी बहतनी चाहिए

विनीत नारायण

इस बार का चुनाव बिल्कुल फैका है। एक तरफ नेतृत्व मोदी के नेतृत्व में भाजपा निहूं नुस्खलापन, कांग्रेस की नाकामियों को चुनावी मुद्रा बनाए हुए हैं वहीं चार दशक में बड़ी सबसे ज्यादा बेरोजगारी, किसान को फसल के उचित वाम न मिलान, बैंडिटा महानगी और तमाम उन बातों की पूरा न करना, जो मोदी जी ने 2014 के 2019 में किया थे-ऐसे मुद्रे में जिन पर भाजपा का इतना सभायाओं में कोई बात नहीं चाही जाती है। न्यायिक पीठ को चाहा गया कि पर्सी को मतदान को देने जोगिम का कम है। इससे गोपनीयता भंग होती है और निकालने पर पर्सी का दुर्लभयोग भी किया जा सकता है। व्यापिकाकर्ता एडीआर ने मतदान और पर्सी की 100 फोसाई छ्रॉस चेकिंग की मांग की है। अब चुनाव की निपक्षता, ईमानदारी बरकरार रहे, मतदानाओं के जेहन में लेशमात्र भी सदैर नहीं होना चाहिए और आयोग की सर्वैधानिक स्वयंचयता भी बनी रहे, तब संदर्भ में अदालत ने तकिया देना है। ईवीएम का लेकर अक्सर प्रलाप मचाया जाना रहा है और चुनाव आयोग को भी कठिन रहा। यह प्रवृत्ति दुष्प्राप्त है। आयोग ने ईवीएम को हैक करने वा उत्तर से सिस्टम से छेड़छाड़ करने के महेनजर सभी राजनीतिक दलों को अमरित विकाया था, कुछ लकड़ गए थे, लोकन कोई भी आपत्ति नहीं उठाए तो कोई विवाह कर रहा है। इसलिए वर्ष 2019 में और इस बार वर्षों में इन्हें सरकारी विषयों की विषयां आना नहीं कर सकती है? न्यायिक पीठ के सामने चुनाव आयोग ने खुलासा किया कि 4 करोड़ ईवीएम वोट और बीवीपैट पर्सीयों के मिलान कराए गए हैं। बहरहाल अदालती फैसले की प्रतीक्षा है।

सावधानी बहतनी चाहिए

विनीत नारायण

विचारमंथन

@Pratahkiran
www.pratahkiran.com
पटना, रविवार, 21 अप्रैल, 2024

मारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को छू सकता है

वहीं, आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 65,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। आज भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चीन, जापान, स्विजरलैंड के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। कोरोना महामारी के बाद आरत का विदेशी मुद्रा भंडार 7,100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से कम हुआ था, परंतु वर्ष 2022 के बाद से यह अब लगातार उतनी ही तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। और, अब तो यह उम्मीदी की जा रही है कि आगे वाले विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कर कर देंगे। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 6,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। यह वर्ष 2004 में 14,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था, वर्ष 2014 में 32,200 करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं वर्ष 2024 में 65,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। भारत के पास 2,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कर कर देता है। यह वर्ष 2004 में 1,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 2,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 1,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 450 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 400 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 350 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 300 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 250 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 200 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 150 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 0.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 0.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 0.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 0.05 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसे बंगलादेश के पास 0.02 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, ज

